जैव ऊर्जा के लिए 70 हजार करोड़ के एमओयू

लखनऊ। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में वैकल्पिक ऊर्जा सेक्टर में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये के समझौते किए गए हैं। इसके तहत करीब 600 करोड़ रुपये के निवेश की 12 योजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन योजनाओं से प्रतिदिन 100 टन बायोगैस और 45 किलोलीटर बायोडीजल का उत्पादन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की हरित ऊर्जा टोकरी को जोड़ते हुए 550 करोड़ रुपये की एक दर्जन निजी क्षेत्र की जैव ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाएं राज्यभर में प्रतिदिन 90 टन से अधिक संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और 44 किलोलीटर (केएल) बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित हैं। बायो एनर्जी परियोजनाओं को अतिरिक्त मुख्य सचिव महेश गुप्ता की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। निजी क्षेत्र इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं

योजनाओं से प्रतिदिन 100 टन बायोगैस और 45 किलोलीटर बायोडीजल का होगा उत्पादन

से आकर्षित है। बायो एनर्जी उत्पादन न केवल पराली (फसल अवशेष) जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि किसानों को एक स्थायी राजस्व स्रोत भी देगा। यूपी ने राज्य बायो एनर्जी नीति-2022 के तहत प्रतिदिन 1,000 टन सीबीजी, 4,000 टन जैव-कोयला (छर्रों), और 2000 किलोलीटर बायोडीजल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस नीति का उद्देश्य पारिस्थितिक संरक्षण में सहायता करने और पराली जलाने के कारण मिट्टी की उर्वरता के नुकसान को रोकने के लिए कृषि अपशिष्ट पर आधारित जैव ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बायो एनर्जी सेगमेंट में राज्य ने 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो

निजी क्षेत्र की दर्जन भर जैव ऊर्जा परियोजनाओं को मिली मंजूरी

राज्य प्रोत्साहन में जैव-कोयला संयंत्र स्थापित करने पर 75,000 रुपये प्रति टन से लेकर अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन और बायोडीजल संयंत्र स्थापित करने पर प्रतिदिन 3 लाख रुपये किलोलीटर से लेकर अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की हरित ऊर्जा टोकरी को जोड़ते हुए 550 करोड़ रुपये की एक दर्जन निजी क्षेत्र की जैव ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। परियोजनाएं राज्य भर में प्रतिदिन 90 टन से अधिक संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और 44 किलोलीटर (केएल) बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित हैं।